दियासलाई कारखानों में बच्चों को काम पर लगाया जाना

*373. श्री छीतूभाई गामित :
श्री नीरेन घोष :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दियासलाई कारखाने 5 वर्ष के बच्चों को काम पर लगाते हैं ;

(ख) क्या कुछ खानों में भी छोटे बच्चों को नौकरी पर रखा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई कानून बनाने का है जिससे कारखाना अथवा खान मालिक ऐसे छोटे छोटे बच्चों को नौकरी पर न रख सकें ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) to (c). Employment of Children Act 1938 and the Factories Act, 1948 do not permit employment of children below the age of 14 years. The Mines Act 1952 prohibits employment of children of less than 16 years in work underground and of children of less than 15 years above ground.

However, it has come to notice of Government that in a report to the Commission on Human Right it is stated that children as young as 5 and 6 can be found working all day long in Sivakasi. Sample surveys carried out by the Labour Bureau go to show that there was no child labour in mines. If such specific cases are brought to the notice of the Government appropriate action under the law would be taken.

श्री छीतूभाई गामित : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं । आज भी हमारे देश में बहुत सी फैक्ट्रीज और खानों में कम उम्र के लड़के मजदूरी का काम कर रहे हैं । कई जगहों पर तो उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है । आई० एल० ओ० ने तीन चार महीने पहले उनके बारे में सर्वेक्षण किया था, उसकी रिपोर्ट भी आई है । उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिन्दुस्तान में करीब 28 हजार कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं और मेघालय की कई स्थानीय कम्पनियां, दियासलाई बनाने वाली कंपनियों में कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं। चाइल्ड-लेबर-इन-इंडिया में भी यह बताया गया है, हिन्दुस्तान के करीब 11 हजार कम उम्र वाले लड़के काम कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी इस रिपोर्ट के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । पिछले पांच साल में कम उम्र वाले लड़कों से काम कराने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष जी, मैंने यह नहीं कहा है कि पांच साल के ऊपर उम्र वाले जो बच्चे हैं, वे काम नहीं कर रहे हैं । मैंने यह कहा है कि यह तमाम हमारी रिपोर्ट्स में है, मैं जानता हूं । स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने इसके बारे में लिखा है । इस संबंध में एक कमेटी भी बनाई गई है, इसकी रिपोर्ट भी आई है । इस रिपोर्ट पर हम एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं और बहुत जल्दी ही स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे ।

श्री छीतूभाई गामित : माननीय अध्यक्ष जी, कई होटलों में कम उम्र वाले लड़कों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है । इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उन लड़कों में से ज्यादातर गरीब और 70 परसेंट ऐसे लड़के हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो कुटुम्ब हैं, उनके रोजगार के लिए क्या कोई प्रबन्ध किया गया है और इन कुटुम्ब के लड़कों को जो मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे वे शिक्षा नही प्राप्त कर सकते है, ऐसे कुटुम्ब के लड़कों के लिए क्या कोई शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाएगा ?

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष महोदय, यह कठिन मसला है, इसको हल करना मुश्किल है, क्योंकि चिल्ड्रन्स काम कर रहे हैं, इस बात से हम इंकार नही कर सकते हैं । एग्रीकल्चर फील्ड में भी लोग काम कर रहे हैं और जहां मैं समझता हूं कि इसके ... (व्यवधान) ... आपके जमाने में तो कुछ नहीं हुआ ... (व्यवधान) ... यह सब आप ही के जमाने का है ... (व्यवधान) ... मैं यह जानता हूं आपने तीन साल तक क्या किया, इस झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता हूं ... (व्यवधान) ... आपके बंगाल में क्या काम हुआ, यह भी मैं जानता हूं ... (व्यवधान) ...

MR. SPEAKER: No cross-talk please..... Mr. Minister, you are not supposed to answer them like this. You should address the chair. When they put a question, only then answer, not now....Order please.

श्री टी० अंजय्या : अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल की जो रिपोर्ट हमें जनवरी में मिली है उसके मुताबिक न कोई एक्शन लिया गया है,

न उस पर कोई सलाह की गई है। उसमें एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में, उनकी वेजेज के बारे में, न्यूट्रीशन-फूड के बारे में रिकमेंडेशन हुई है, इन रिकमेंडेशन्स पर स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके, यदि इसके 'ला' में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, वह करके, इसको इम्प्लीमेंट करने का पूरी कोशिश करेंगे।

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Now Mr. Niren Ghosh.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Order please. Mr. Niren Ghosh is on his legs.

(Interruptions)

SHRI NIREN GHOSH: Sir, we know that there are employer-oriented trade union leaders. I do not know whether Shri Anjiah is one of them. Why should he get excited? Was it proper for him? Coming to brass-tacks, he has not answered the question. I.L.O. has given a figure about the number of child labour. What is the information at his disposal? He can corroborate it, or differ from it. In how many States is child labour being employed? Has the Government started any case since it came to power 5 months ago? Will he take any steps? If there are 70 per cent of the people below the poverty line, they might be forced to give their childern in bondage to those people. In any case, how many cases did he start and enquire into; and has anybody been sent to jail? What steps does he now propose to take, to uproot this evil for ever?

श्री टी॰ अंजय्या : मैं अब अगर कुछ कहूंगा तो अपोजीशन लीडर्स को गुस्सा आ जायेगा। इन लोगों ने एक्शन्ज लिये हैं या प्रासिक्यूशन्ज किये हैं, हमें मालूम है। एक-दो स्टेट को छोड़ कर किसी स्टेट में कुछ नहीं हुआ है। मद्रास में कुछ काम हुआ है, वहां कुछ एक्शन्ज लिए गये हैं। मगर जैसे आई॰ एल॰ ओ॰ की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है, वह आ गई है। जनवरी में हमारे आफिसर्ज की जो कमेटी बनी थी उस की रिपोर्ट भी आ गई है और उस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट्स को करना है, हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक सैल बना कर इस को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे। इस बारे में हम जरूरी स्टेप्स उठा रहे हैं।

SHRI NIREN GHOSH: He is giving an assurance. He is not answering my question. Sir, do you think he has answered it?

MR. SPEAKER: He said it was a State subject. They are asking the States.

SHRI NIREN GHOSH: It is a concurrent one.

श्री रामविलास पासवान : आप लाख कानून बना लेंगे, लेकिन जब तक जो बेसहारा लड़के हैं, जिन के मां बाप को भी रोजगार नहीं मिलता है, उन के बेटे को कहां से रोजगार मिल जायगा। ऐसी हालत में 5-10 साल के बच्चों को नौकरी करने से, फैक्ट्री में जाने से आप रोक नहीं सकते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि जो लड़के बेसहारा हैं, भीख मांगते हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, क्या केन्द्रीय सरकार उनके लिए कोई योजना बनायेगी? चाहे एक बार में यह काम न हो, फेज वाइज हो, इस साल में हम इतने लड़कों को पढ़ायेंगे, उनको अच्छा नागरिक बनायेंगे- इस तरह की कोई योजना क्या सरकार के पास है?

श्री टी॰ अंजय्या : इस प्रश्न का फैक्ट्रीज में काम करने वाले, माइन्ज में काम करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। इस लिए जो प्रश्न आप ने पूछा है, उस के लिए नोटिस देंगे, तो जवाब दूंगा।

श्री मलिक एम॰ एम॰ ए॰ खां : मंत्री महोदय ने कहा है कि जो मेन क्वेश्चन है उस से इस सवाल का ताल्लुक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो बच्चे पांच साल से ऊपर की उम्र के हैं अपने मां-बाप की गरीबी की वजह से गुजर के लिए मिलों में या खेतों में या दूसरे तरीके से मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके बारे में कोई कानूनी पाबंदी लगाने के बजाय क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा इंतजाम करेगी जिससे कि उन्हें अपनी उम्र से ज्यादा काम न करना पड़े और उनका कोई दूसरा इंतजाम भी हो सके?

श्री टी॰ अंजय्या : यह सजेशन है इसके बारे में

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि 1977 के पहले कितनी चाइल्ड लेबर थी और 1977 के बाद कितनी चाइल्ड लेबर बढ़ी?

श्री टी॰ अंजय्या : यह मसला बड़ा कठिन मसला है। यह जो फैक्ट्री में वर्किंग करने के लिए आते हैं तो ऐसा होता है कि बच्चे जो एम्प्लाएड होते हैं उनको छिपा दिया जाता है। यह मसला एक गरीबी का मसला है और इस मसले को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे सिर्फ कानूनी एक्शन लेने से यह हल नहीं होगा बल्कि और दूसरे स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं आया।

SHRI N. K. SHEJWALKAR: You must protect the House. To the last three questions, no relevant replies have been given.

MR. SPEAKER: I am looking after the whole House.....

SHRI DIGVIJAY SINH: Almost 15,000 children in Gujarat State do diamond polishing. By the time they reach the age of 15, they lose their eye sight. Is the government aware of this thing and what steps have been taken against this?

श्री डी० मंजयया : मैंने कहा कि यह स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटशन करने का मसला है। मैंने यह नहीं कहा है कि इसमें एक्सप्लाइटेशन नहीं है, इसमें एक्सप्लाइटेशन है। इसमें जितना एक्शन लिया जाना चाहिए वह हम लेंगे। जो रिपोर्ट आयी है उसको स्टडी करके ही एक्शन लिया जा सकता है।

Agreement with Bangladesh for River Route service to Karimganj

*374. SHRI SANTOSH MOHAN DEV: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed with Bangladesh Government through river route service to Karimganj (Bangladesh); and

(b) if so, the date from which it is likely to restart?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT AND TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) Under the Protocol on Inland Water Transit and Trade signed by the Governments of India and Bangladesh in November, 1972 river services on Calcutta-Karimganj-Calcutta route are already being operated.

(b) Calcutta-Karimganj river service was resumed from 19th May, 1975. This service is continued for about 5 months in a year when the water depth is sufficient for economic operation in this route for the existing vessels of the Corporation.

SHRI SANTOSH MOHAN DEV: In his reply the Minister has said that there is an agreement with Bangladesh from 1972. From 1972 till today, how many times the rivers have been operated from Calcutta to Karimganj? In view of the present position in Assam, the economic condition of Cachar, Mizoram and Tripura is so bad that essential commodities are being sold at the highest prices as compared to the whole country. What steps his Ministry proposes to take to make this service a regular one?

SHRI A. P. SHARMA: I have already said that the service has been now resumed; and I suppose it will be a regular service. But the difficulty is that on the side of Bangladesh, the water depth is not sufficient that we can carry on the service regularly. We are going to have a meeting with the Bangladesh Government. There is a standing committee between the Governments of India and Bangladesh and in that meeting, we are going to raise this question as to how they are going to improve the position on the other side so that we can have a continuous service.

MR. SPEAKER: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Improvement in Delhi Hospitals towards Patients

*369. SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY: Will the Minister of HEALTH be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the imperative necessity to make the Government doctors in Delhi to show positive response and responsibility in action towards the patients in general;

(b) what other immediate improvements Government propose to make in hospitals in Delhi; and

(c) the corrective steps taken so far?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND):